[2015] 8 एस. सी. आर. 422

ए. बी. सी.

बनाम

द स्टेट (एन. सी. टी. ऑफ दिल्ली)

(सिविल अपील संख्या 5003/2015)

06 जुलाई, 2015

[विक्रमजीत सेन और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.)

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890-धारा 7 और 11-अविवाहित ईसाई माँ द्वारा अपने बच्चे के संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन-अविवाहित माँ द्वारा बच्चे के अनुमानित पिता को धारा 11 के तहत नोटिस देने की आवश्यकता। अभिनिर्धारित किया: बच्चे की स्वाभाविक माँ, जिसकी वह एकमात्र देखभाल करने वाली है, द्वारा पसंद की गई संरक्षकता या अभिरक्षा याचिका के संबंध में अनुमानित पिता को नोटिस देने की कोई अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है-धारा 11 ऐसी स्थिति पर लागू होती है जहां बच्चे की संरक्षकता किसी तीसरे पक्ष द्वारा मांगी जाती है, जिससे बच्चे के स्वाभाविक अभिभावक के विचारों को स्वीकार करने के

लिए गोद लेने में दिए गए बच्चे के कल्याण के लिए यह आवश्यक हो जाता है-संरक्षक न्यायालय अपने द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को वापस ले और बच्चे के अनुमानित पिता को नोटिस दिए बिना संरक्षकता के लिए माँ के आवेदन पर तेजी से विचार करे।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. दुनिया भर में फैले विभिन्न नागरिक और सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों के साथ-साथ भारत के भीतर विभिन्न कानूनों में प्रमुख कानूनी विचार विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे की मां को संरक्षकता और संबंधित अधिकार प्रदान करना है। जाहिर है, माँ अपनी संतान की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए हिंदी में 'ममता' शब्द द्वारा उपयुक्त और व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। इसके अलावा, उसकी मातृत्व को मान्यता देने से पितृत्व निर्धारित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में, जहां पिता ने अपनी संतानों के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई है, उसे कानूनी मान्यता देना व्यर्थ की कवायद होगी। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट करने का ध्यान रखा है कि यदि उसके बेटे के पिता ने अपने बेटे में कोई रुचि दिखाई है, तो वह मुकदमे में उसकी भागीदारी पर आपत्ति नहीं करेगी, या इसकी परिणति की स्थिति में, अभिरक्षा मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा। हालाँकि संरक्षक न्यायालय को ऐसी किसी रियायत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माता का इस बात पर जोर देना कि पिता

को सार्वजनिक रूप से सूचित नहीं किया जाना चाहिए, अनुचित नहीं लगता है। [पैरा 9] [435-सी-जी]

1.2 यह आवश्यक है कि माँ के अधिकारों पर भी उचित विचार किया जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि अपीलार्थी को अपने बच्चे के पिता के नाम और विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपनी संतानों का ध्यान रखेगा और उस बच्चे के कल्याण के लिए चिंतित होगा जिसे वह दुनिया में लाया है; तत्काल मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा, भारत में ईसाई अविवाहित माताएं अपने हिंदू समकक्षों की तुलना में वंचित हैं, जो अपने अवैध बच्चों के स्वाभाविक संरक्षक हैं, केवल अपने मातृत्व के कारण, बिना किसी सूचना की आवश्यकता के। यह रेखांकित करना उचित होगा कि निदेशक सिद्धांत एक समान नागरिक संहिता के अस्तित्व की कल्पना करते हैं, लेकिन यह एक अनुत्तरित संवैधानिक अपेक्षा बनी हुई है। [पैरा 11] [436-सी-एफ]

1.3 अपने बच्चे के जीवन में शामिल होने का पिता का अधिकार छीन लिया जा सकता है यदि धारा 11 को इस तरह से पढ़ा जाए कि उसे नोटिस नहीं दिया जाए, लेकिन बच्चे के जीवन में उसकी भागीदारी की कमी को देखते हुए, माता या उसके बच्चे के अधिकारों पर उसके अधिकारों

को प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि अपीलार्थी ने पहले ही एक राष्ट्रीय दैनिक में एक प्रकाशन के माध्यम से आम जनता को नोटिस जारी कर दिया है और एक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि उसके संरक्षकता अधिकारों को रद्द, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है यदि किसी भी समय बच्चे के पिता उन्हें आपत्ति करते हैं, तो पिता के अधिकारों, नहीं तो कर्तव्य को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है। तत्काल मामले में, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यदि अपीलकर्ता को पिता की पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, या यह कि बच्चे के हित में अदालत का नोटिस अनिवार्य है, तो बच्चे के कल्याण को कम किया जाएगा। इसके विपरीत, यह बच्चे को सामाजिक कलंक और अनावश्यक विवाद से अच्छी तरह से बचा सकता है। [पैरा 12,13] [436-जी, एच; 432-ए-डी]

लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ 1985 (पूरक) एस. सी. सी. 701:1985 पूरक एस. सी. आर. 71; गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (1999) 2 एस. सी. सी. 228:1999 (1) एस. सी. आर. 669- संदर्भित।

1.4 चूंकि अधिनियम का उद्देश्य बच्चे के कल्याण की रक्षा करना है, इसलिए धारा 11 की प्रयोज्यता को तदनुसार पढ़ना होगा। ऐसे मामले में जहां अभिभावक में से कोई एक अपने बच्चे के अभिभावक के रूप में

नियुक्ति के लिए न्यायालय में याचिका दायर करता है, धारा 11 के प्रावधान सीधे लागू नहीं होंगे। धारा 11 उस स्थिति पर लागू होती है जहां किसी बच्चे की संरक्षकता किसी तीसरे पक्ष द्वारा मांगी जाती है, जिससे गोद लेने के दौरान बच्चे के कल्याण के लिए बच्चे के स्वाभाविक अभिभावक के विचार प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। विवाह से पैदा हुए और केवल उसकी माँ द्वारा उठाए गए बच्चे के हितों की रक्षा के लिए एक असंबद्ध पिता के विचार आवश्यक नहीं हैं। अभिभावक को सूचना नहीं भेजी जानी चाहिए, क्योंकि इससे गोद लिए जा रहे बच्चे के भविष्य और हितों को खतरे में डालने की संभावना थी। इसलिए, अभिभावक के अधिकारों की परवाह किए बिना, विचार के लिए एकमात्र कारक नाबालिग बच्चे का कल्याण है। [पैरा 15] [438-डी-एफ]

1.5 धारा 11 विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है; अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकताओं में ढील देने में कोई नुकसान या बुराई नहीं है। अधिनियम में "अभिभावक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी व्याख्या अवैध बच्चों के मामले में की गई है, जिनके एकमात्र देखभाल करने वाले उनके अभिभावक में से एक हैं, जिसका मुख्य रूप से मतलब केवल वही अभिभावक है। संरक्षकता या अभिरक्षा आदेश कभी भी स्थायित्व या अंतिमता प्राप्त नहीं करते हैं और किसी भी समय, नाबालिग बच्चे के लिए वास्तव में चिंतित किसी भी व्यक्ति द्वारा सवाल

किया जा सकता है, यदि बच्चे का कल्याण खतरे में है। इसलिए, असंबद्ध अभिभावक को संरक्षक न्यायालय से उसके आदेशों को रद्द करने, बदलने या संशोधित करने के लिए संपर्क करने से नहीं रोका जाता है, यदि बच्चे के सर्वोत्तम हितों से ऐसा संकेत मिलता है। इस प्रकार, बच्चे की स्वाभाविक माँ द्वारा पसंद की गई संरक्षकता या अभिरक्षा याचिका के संबंध में अनुमानित पिता को सूचना देने की कोई अनिवार्य और अपरिवर्तनीय प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है, जिसकी वह एकमात्र देखभाल करने वाली है। [पैरा 16] [438-एच; 439-ए-सी]

1.6 यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चे के अपने अभिभावक की पहचान जानने के अधिकार को निरस्त, कमजोर, समझौता या खतरे में न डाला जाए। इस अधिकार को सुरक्षित करने और संरक्षित करने के लिए, अपीलार्थी का साक्षात्कार लिया गया और उसके बेटे को पिता के नाम का खुलासा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उसने इस अदालत को कुछ विवरणों के साथ उसके नाम का खुलासा किया; उसने कहा कि उसे उसके बारे में आगे कोई जानकारी नहीं है। इन विवरणों को एक लिफाफे में रखा गया है और विधिवत सील कर दिया गया है, और केवल इस न्यायालय के एक विशिष्ट निर्देश के अनुसार पढ़ा जा सकता है। [पैरा 18] [443-सी-डी]

1.7 अपीलार्थी ने अपने लगभग पाँच साल के बेटे के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। इससे भविष्य में बच्चे के लिए समस्याएं पैदा होनी तय है। इस संबंध में, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष या नीचे की किसी भी अदालत के समक्ष कोई राहत नहीं मांगी है। कानून में यह एक गलत धारणा है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करना अपीलार्थी के लिए उसकी संरक्षकता याचिका में सफल होने के लिए एक तार्किक परिणाम होगा। क्यूरियल फिएट के कारण, अब बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने के साथ-साथ नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदनों में पिता का नाम बताना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, इन दोनों मामलों में, अभी भी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है। यह निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई एकल अभिभावक/अविवाहित माँ अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करती है, तो संबंधित अधिकारी उसे केवल इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई अदालत का निर्देश न हो। [पैरा 19] [443-ई-एच; 444-ए-बी]

1.8 संरक्षक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था कि उन्हें अपने अभिभावक के क्षेत्राधिकार का निर्वहन करने के लिए कहा गया था। न्यायालय के समक्ष

संरक्षकता याचिका रखे जाने पर, संबंधित बच्चा अभिभावक की अनन्य अभिरक्षा में रहना बंद कर देता है; उसके बाद, जब तक वयस्कता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक बच्चा संरक्षकता में बना रहता है। एक ऐसी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के बाद जो एक बच्चे के भविष्य और कल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, नीचे की अदालतों को बच्चे से संबंधित सभी समस्याओं, जटिलताओं और जटिलताओं पर विचार किए बिना केवल याचिका को खारिज करने में अपने कर्तव्य में लापरवाही के रूप में देखा जा सकता है। संरक्षक न्यायालय को उसके द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया जाता है और उसके बाद बच्चे के अनुमानित पिता को नोटिस दिए बिना संरक्षकता के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर तेजी से विचार करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 20,21] [444-डी-एच]

जॉय डी. ब्रियोन्स बनाम मैरिसेल पी. मिगुएल और अन्य जी. आर. सं. 156343-संदर्भित।

प्रकरण कानून संदर्भ

1985 पूरक एस. सी. आर. 71 का पैरा 13 संदर्भित।

1999 (1) एस. सी. आर. 669 का पैरा 14 संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5003/2015

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2011 के एफ. ए. ओ. संख्या 346 में दिनांकित 08.08.2011 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता के लिए इन्दु मल्होत्रा, अंशुमन सिंह, वरुण सिंह, ईशा महापात्रा, प्रशांत सिंह, अजय विक्रम सिंह, इमरान आलम और रंजीत।

उत्तरदाता के लिए सिद्धार्थ लूथरा, (एसी), विराज गांधी, पी. के. डे, गुणवंत दारा, सरोज बाला, डी. एस. महारा और बी. वी. बलराम दास।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

विक्रमजीत सेन, जे. 1. मौलिक महत्व और गद्यात्मक प्रक्रियात्मक उत्पत्ति का एक कानूनी संकेत हमारे सामने प्रस्तुत होता है। पहेली यह है कि क्या एक अविवाहित माँ के लिए यह अनिवार्य है कि वह विशेष रूप से उस बच्चे के अनुमानित पिता को सूचित करे जिसे उसने अपने बच्चे के अभिभावक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी याचिका के बारे में बताया है। आम धारणा यह होगी कि तीन प्रतिस्पर्धी कानूनी हित उत्पन्न होंगे, अर्थात्, माँ और पिता और बच्चे के। हम सोचते हैं कि यह केवल अंतिम है जो निर्णायक है, क्योंकि वास्तव में अभिभावक के पास केवल कानूनी दायित्व हैं। एक बच्चा, जैसा कि विभिन्न कानूनी मंचों में सर्वव्यापी रूप से व्यक्त किया गया है, एक सामान या गेंद नहीं है जिसे एक अभिभावक से

दूसरे अभिभावक को भेजा या स्थानांतरित किया जा सके। अदालत हिरासत या संरक्षकता के झगड़ों में अभिभावक के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है; यह दो वयस्कों के असहाय बच्चे के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाता है जिनके व्यक्तिगत मतभेदों और दुश्मनी ने उनके बच्चे के भविष्य से प्राथमिकता छीन ली है।

2. अनुमति दी गई। यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांकित 8.8.2011 निर्णय के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसने अपीलार्थी की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जो एक अविवाहित माँ है, यह मानते हुए कि उसके संरक्षकता आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अपने बच्चे के पिता के नाम और पते का खुलासा नहीं करती है, जिससे अदालत उसे प्रक्रिया जारी करने में सक्षम हो जाती है। अपीलार्थी के अनुरोध के अनुसार, उसकी पहचान और व्यक्तिगत विवरण के साथ-साथ उसके बेटे के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है।

3. अपीलार्थी, जो ईसाई धर्म का पालन करता है, अच्छी तरह से शिक्षित, लाभकारी रूप से नियोजित और आर्थिक रूप से सुरक्षित है। उन्होंने 2010 में अपने बेटे को जन्म दिया, और बाद में अपने पिता की किसी भी सहायता या भागीदारी के बिना उसका पालन-पोषण किया। अपनी सभी बचत और अन्य बीमा पॉलिसियों में अपने बेटे को नामित करने की

इच्छा रखते हुए, उन्होंने इस दिशा में कदम उठाए, लेकिन उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें या तो पिता का नाम घोषित करना होगा या अदालत से संरक्षकता/गोद लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद उन्होंने अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 (अधिनियम) की धारा 7 के तहत संरक्षक न्यायालय के समक्ष उन्हें अपने बेटे का एकमात्र अभिभावक घोषित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। अधिनियम की धारा 11 में अभिभावक की नियुक्ति से पहले बच्चे के अभिभावक को नोटिस भेजने की आवश्यकता है। अपीलार्थी ने एक दैनिक समाचार पत्र, वीर अर्जुन, दिल्ली संस्करण में याचिका का एक नोटिस प्रकाशित किया है, लेकिन पिता का नाम लेने के सख्त खिलाफ है। उसने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि यदि भविष्य में किसी भी समय उसके बेटे के पिता उसके संरक्षकता के संबंध में कोई आपत्ति उठाते हैं, तो उसे रद्द या बदला जा सकता है जैसा कि स्थिति की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, गार्जियन कोर्ट ने उसे पिता के नाम और ठिकाने का खुलासा करने का निर्देश दिया और उसके ऐसा करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप, 19.4.2011 पर उसके संरक्षकता आवेदन को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की अपील को इस तर्क पर सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था कि उसके एकल माँ होने के आरोप का फैसला पिता को नोटिस जारी किए जाने के बाद ही किया जा सकता है; कि एक स्वाभाविक पिता को अपने बच्चे के कल्याण और अभिरक्षा में रुचि हो सकती है, भले ही

कोई विवाह न हो; और यह कि किसी भी मामले का फैसला आवश्यक पक्ष के अभाव में नहीं किया जा सकता है।

4. अपीलार्थी की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री इन्दु मल्होत्रा ने हमारे समक्ष जोरदार तर्क दिया है कि अपीलार्थी नहीं चाहता कि उसके बच्चे का भविष्य उसके पितृत्व के संबंध में किसी भी विवाद से प्रभावित हो, जिसका परिणाम निश्चित रूप से तब होगा जब पिता बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दे। यह एक परेशान करने वाली वास्तविकता है क्योंकि पिता पहले से ही शादीशुदा है और उसके द्वारा विवाह से एक बच्चे के पिता बनने की घोषणा के बारे में किसी भी प्रचार का उसके वर्तमान परिवार पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। उसके और उसके बच्चे के लिए गंभीर सामाजिक जटिलताएँ होंगी। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, अभिभावक की नियुक्ति के लिए नाबालिग का हित ही एकमात्र प्रासंगिक कारक है और माता और पिता के अधिकार इसके अधीन हैं। इस परिदृश्य में, अपीलार्थी को तुरंत अभिभावक के रूप में नियुक्त करके बच्चे के हित की सर्वोत्तम सेवा की जाएगी। इसके अलावा, यह भी सामने रखा जाता है कि अगर उसे अपने बच्चे के पिता के नाम और विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा। सुश्री मल्होत्रा ने इस अपील पर बहुत मेहनत से तर्क दिया है, पूरी तरह से इस बात से अवगत हैं कि जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह

दूरगामी आयामों का है। यही वह विशेषता है जिसने हमें न्यायमित्र नियुक्त करने की समीचीनता के बारे में आश्वस्त किया, और श्री सिद्धार्थ लूथरा ने इन भारी कर्तव्यों का उत्साहपूर्वक निर्वहन किया है, जिसके लिए हमें तुरंत अपना ऋण दर्ज करना चाहिए।

5. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 पर संक्षिप्त रूप से विचार करना उचित होगा। यह अधिनियम, जो भारत में ईसाइयों पर लागू होता है, उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा संरक्षकों को क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाना है। धारा 7,11 और 19 संदर्भ की सुविधा के लिए निष्कर्षण के योग्य हैं।

"7. संरक्षकता के बारे में आदेश देने की अदालत की शक्ति

(1) जहां अदालत का यह समाधान हो जाता है कि एक आदेश नाबालिग के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए-

(ए) उसके व्यक्ति या संपत्ति, या दोनों के संरक्षक की नियुक्ति, या

(बी) किसी व्यक्ति को ऐसा संरक्षक घोषित करना, अदालत तदनुसार आदेश दे सकती है।

(2) इस धारा के तहत एक आदेश का अर्थ किसी ऐसे अभिभावक को हटाना होगा जिसे वसीयत या अन्य साधन द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है या जिसे अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है।

(3) जहां किसी संरक्षक को वसीयत या अन्य लिखत द्वारा नियुक्त किया गया है या अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है, इस धारा के तहत किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त रूप से नियुक्त या घोषित संरक्षक की शक्तियां समाप्त नहीं हो जाती हैं। आवेदन पत्र का विवरण धारा 10 में निहित है और संरक्षकता आवेदन पर लागू होने वाली प्रक्रिया धारा 11 में निर्धारित की गई है।

11. आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया

(1) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदन पर कार्यवाही करने का आधार है, तो वह उसकी सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित करेगा, और आवेदन की और सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि की सूचना देगा-

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14) में निर्देशित तरीके से लागू किया जाएगा।

(i) नाबालिग के अभिभावक, यदि वे किसी ऐसे राज्य में रहते हैं, जिसमें यह अधिनियम लागू होता है;

(ii) याचिका या पत्र में नामित व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसका नाम नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति की अभिरक्षा या कब्जा है;

(iii) नियुक्त किए जाने वाले या अभिभावक घोषित किए जाने वाले आवेदन या पत्र में प्रस्तावित व्यक्ति, जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं आवेदक न हो; और

(iv) कोई अन्य व्यक्ति जिसे अदालत की राय में आवेदक की विशेष सूचना दी जानी चाहिए; और

(ख) न्यायालय के किसी विशिष्ट भाग और नाबालिग के निवास पर तैनात किया जाए, और अन्यथा इस तरह से प्रकाशित किया जाए कि अदालत, इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, उचित समझे।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकती है कि जब धारा 10, उप-धारा (1) के तहत याचिका में वर्णित संपत्ति का कोई भी हिस्सा ऐसी भूमि है जिसका वार्ड न्यायालय अधीक्षण ग्रहण कर सकता है, तो न्यायालय उस कलेक्टर को, जिसके जिले में नाबालिग सामान्य रूप से रहता है, और प्रत्येक कलेक्टर को, जिसके जिले में भूमि का कोई भी हिस्सा स्थित है, उपरोक्त नोटिस जारी कराएगा और कलेक्टर किसी भी तरह से नोटिस प्रकाशित कराएगा जो वह उचित समझे।

(3) अदालत या कलेक्टर द्वारा उप-धारा (2) के तहत दी गई या प्रकाशित किसी भी सूचना की सेवा या प्रकाशन के लिए कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा।

धारा 19 का महत्व है, भले ही शिशु पुत्र स्वतंत्र रूप से किसी संपत्ति का मालिक नहीं है या उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से नाबालिग के पिता का उल्लेख है। यह इस प्रकार हैः

19. कुछ मामलों में अदालत द्वारा संरक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी.

इस अध्याय की कोई बात न्यायालय को ऐसे नाबालिग की संपत्ति का संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी जिसकी संपत्ति वार्ड न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन है या उस व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी-

(क) किसी नाबालिग का जो विवाहित महिला है और जिसका पति अदालत की राय में उसके व्यक्ति का संरक्षक होने के लिए अयोग्य नहीं है; या

(ख) किसी नाबालिग का जिसका पिता जीवित है और अदालत की राय में नहीं है, वह नाबालिग के व्यक्ति का संरक्षक होने के लिए अयोग्य है; या

(ग) किसी ऐसे नाबालिग का संरक्षक जिसकी संपत्ति नाबालिग के व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त करने के लिए सक्षम वार्ड न्यायालय के पर्यवेक्षण के तहत है।

हमें तुरंत नामकरण में अंतर को रेखांकित करना चाहिए, अर्थात धारा 11 में 'अभिभावक' और धारा 19 में 'पिता', जिसे हम मानते हैं कि नजरअंदाज करना खतरनाक होगा।

6. राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि धारा 11 में अभिभावक की नियुक्ति से पहले नाबालिग के 'अभिभावक' को नोटिस देने की आवश्यकता है और धारा 19 के अनुसार, यदि नाबालिग का पिता जीवित है और अदालत की राय में बच्चे का अभिभावक होने के लिए अयोग्य नहीं है तो अभिभावक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अधिनियम के अनुसार है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि यह व्याख्या धारा 7 को व्यापक महत्व नहीं देती है, जो कि अधिनियम का सार है। हालांकि, अधिनियम के इरादे और व्याख्या पर चर्चा करने से पहले, यह समझने में सहायक होगा कि जिस तरह से एक ही मुद्दे को अन्य कानूनों में निपटाया गया है और दुनिया भर में विभिन्न कानूनी प्रणालियों का विस्तार किया गया है।

7. हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) अवैध बच्चों के प्राकृतिक अभिभावकों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान

करती है, और इस संबंध में पिता पर मां को प्रधानता देती है। मुसलमान कानून अवैध बच्चों की अभिरक्षा माँ और उसके रिश्तेदारों को देता है। कानून इस सिद्धांत का पालन करता है कि बच्चे की मातृत्व उस महिला में स्थापित होती है जो उसे जन्म देती है, चाहे जन्म देने वाले के साथ उसके संबंध की वैधता कुछ भी हो। हालाँकि, पितृत्व स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट है, विशेष रूप से जहाँ बच्चा विवाह की संतान नहीं है। इसके अलावा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 के अनुसार, जो भारत में ईसाइयों पर लागू होती है, एक अवैध बच्चे के मूल का अधिवास उस देश में है जिसमें उसके जन्म के समय उसकी माँ अधिवासित है। यह इंगित करता है कि संबंधित बच्चे के पिता की तुलना में मां को प्राथमिकता, वरीयता और प्रमुखता दी जाती है।

8. यूनाइटेड किंगडम में, बाल अधिनियम 1989 अभिभावक की जिम्मेदारी आवंटित करता है, जिसमें बच्चे और उसकी संपत्ति पर अभिभावक के सभी अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां, जिम्मेदारियां और अधिकार शामिल हैं। उस अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार, अविवाहित अभिभावक से पैदा हुए बच्चे की अभिभावक की अभिरक्षा सभी मामलों में मां के साथ है, और इसके अतिरिक्त पिता के साथ है बशर्ते उसने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिम्मेदारी हासिल की हो। जिम्मेदारी हासिल करने के लिए, उसे बच्चे के पिता के रूप में पंजीकरण करना होगा,

मां के साथ अभिभावक की जिम्मेदारी के समझौते को निष्पादित करना होगा या उसे बच्चे पर अभिभावक की जिम्मेदारी देते हुए अदालत का आदेश प्राप्त करना होगा। यू. एस. ए. में, प्रत्येक राज्य में अलग-अलग बाल अभिरक्षा कानून हैं, लेकिन मुख्य रूप से मां के पास बच्चे के जन्म के समय से पूर्ण कानूनी और शारीरिक अभिरक्षा है। जब तक कोई अविवाहित पिता बच्चे पर अपना पितृत्व स्थापित नहीं करता है, तब तक उसके लिए आम तौर पर माता के अभिरक्षा के तरजीही दावों को हराना या अभिभूत करना मुश्किल होता है। हालांकि, कुछ राज्यों का मानना है कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों अभिभावक की संयुक्त अभिरक्षा है, चाहे वे विवाहित हों या नहीं। आयरलैंड में, शिशु संरक्षकता अधिनियम, 1964 की धारा 6 (4) में आदेश दिया गया है-"एक अवैध शिशु की माँ शिशु की संरक्षक होगी"। जब तक माँ एक वैधानिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं होती है, तब तक एक अविवाहित पिता को अपने बच्चे का कानूनी अभिभावक बनने के लिए अदालत में आवेदन करना होगा। फिलीपींस के परिवार संहिता के अनुच्छेद 176 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "अवैध बच्चे उपनाम का उपयोग करेंगे और अपनी माँ के अभिभावक के अधिकार के तहत होंगे, और इस संहिता के अनुरूप समर्थन करने के हकदार होंगे।" यह स्थिति इस बात की परवाह किए बिना प्राप्त होती है कि पिता पितृत्व स्वीकार करता है या नहीं। 2004 में, जॉय डी. ब्रियोन्स बनाम मैरिसेल पी. मिगुएल

एट अल, जी. आर. संख्या 156343 में फिलीपींस का सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक अवैध बच्चा माँ के एकमात्र अभिभावक के अधिकार में है। न्यूजीलैंड में कानून, जैसा कि बच्चों की देखभाल अधिनियम, 2004 की धारा 17 में निर्धारित किया गया है, यह है कि बच्चे की माँ एकमात्र अभिभावक है यदि वह बच्चे के गर्भधारण से शुरू होने और बच्चे के जन्म के साथ समाप्त होने की अवधि के दौरान किसी भी समय बच्चे के पिता के साथ विवाहित, या नागरिक संघ में नहीं है, या वास्तविक भागीदार के रूप में नहीं रह रही है। दक्षिण अफ्रीका में, 2005 के बाल अधिनियम सं. 38 में अभिभावक की जिम्मेदारी में जिम्मेदारी और अधिकार शामिल हैं (ए) बच्चे की देखभाल करना; (बी) बच्चे के साथ संपर्क बनाए रखना; (सी) बच्चे के अभिभावक के रूप में कार्य करना; और (डी) बच्चे के रखरखाव में योगदान करना। एक बच्चे की जैविक माँ, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, के पास बच्चे के संबंध में अभिभावक की पूरी ज़िम्मेदारियाँ और अधिकार हैं। पिता के लिए अभिभावक की पूरी जिम्मेदारी है यदि वह मां से विवाहित है, या यदि वह बच्चे के गर्भधारण के समय, या बच्चे के जन्म के समय या बीच में किसी भी समय उसके साथ विवाहित था, या यदि बच्चे के जन्म के समय वह स्थायी जीवन-साझेदारी में मां के साथ रह रहा था, या यदि वह (i) बच्चे के पिता के रूप में पहचाने जाने के लिए धारा 26 के संदर्भ में पहचान करने या सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए सहमति देता है या प्रथागत कानून के

संदर्भ में हर्जाना का भुगतान करता है; (ii) उचित अवधि के लिए बच्चे के पालन-पोषण में योगदान करने के लिए सद्भावना से योगदान देता है या योगदान करने का प्रयास करता है; और (iii) इस संबंध में खर्चों में योगदान करने के लिए सद्भावना से योगदान देता है या प्रयास करता है। यह परिप्रेक्ष्य इंगित करता है कि प्रमुख स्थिति यह है कि यह अविवाहित माँ है जो अपने बच्चों के संबंध में प्राथमिक अभिरक्षा और संरक्षक अधिकार रखती है और पिता को केवल बच्चे के पिता होने के कारण समान स्थिति से सम्मानित नहीं किया जाता है। यह विश्लेषण हमें भारत में मौजूद कानून की सार्थक, गतिशील और स्थायी व्याख्या करने में सहायता करेगा।

9. इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि दुनिया भर में फैले विभिन्न नागरिक और सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों के साथ-साथ भारत के भीतर विभिन्न कानूनों में प्रमुख कानूनी विचार विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे की मां को संरक्षकता और संबंधित अधिकार प्रदान करना है। जाहिर है, माँ अपनी संतान की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए हिंदी में 'ममता' शब्द द्वारा उपयुक्त और व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। इसके अलावा, उसकी मातृत्व को मान्यता देने से पितृत्व निर्धारित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में, जहां पिता ने अपनी संतानों के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई है, उसे कानूनी मान्यता देना व्यर्थ

की कवायद होगी। आज के समाज में, जहां महिलाएं तेजी से अपने बच्चों को अकेले पालने का विकल्प चुन रही हैं, हम एक अनिच्छुक और चिंता न करने वाले पिता को एक अन्यथा व्यवहार्य पारिवारिक केंद्र पर थोपने का कोई उद्देश्य नहीं देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़ना चुना है, वह बच्चे की भलाई के लिए आवश्यक घटक नहीं है। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट करने का ध्यान रखा है कि यदि उसके बेटे के पिता ने अपने बेटे में कोई रुचि दिखाई है, तो वह मुकदमे में उसकी भागीदारी पर आपत्ति नहीं करेगी, या इसकी परिणति की स्थिति में, अभिरक्षा मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा। हालाँकि संरक्षक न्यायालय को ऐसी किसी रियायत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिता को सार्वजनिक रूप से सूचित नहीं करने पर जोर देने में माँ का इरादा हमें अनुचित नहीं लगता है।

10. हम यह जोड़ना आवश्यक समझते हैं कि अन्य देशों में कानून के हमारे विश्लेषण का उद्देश्य इस बात की समग्र समझ पर पहुंचना था कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों ने महसूस किया कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा। जैसा कि विद्वान वकील ने सुझाव दिया, ईसाई कानून के सिद्धांतों को समझना नहीं था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यह एक प्रमुख आवश्यकता है कि धर्म को कानून से दूर रखा जाए। इसलिए, हमारे सामने कार्य देश के कानून की व्याख्या करना है, न कि पक्षों के धर्म के सिद्धांतों

के आलोक में, बल्कि विधायी इरादे और प्रचलित मामले के कानून को ध्यान में रखते हुए।

11. यह आवश्यक है कि माँ के अधिकारों पर भी उचित विचार किया जाए। जैसा कि अपीलार्थी की वरिष्ठ वकील सुश्री मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया है कि यदि अपीलार्थी को अपने बच्चे के पिता के नाम और विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपनी संतानों का ध्यान रखेगा और उस बच्चे के कल्याण के लिए चिंतित होगा जिसे वह दुनिया में लाया है; वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि वे वर्तमान में चित्रित करते हैं। इसके अलावा, भारत में ईसाई अविवाहित माताएं अपने हिंदू समकक्षों की तुलना में वंचित हैं, जो अपने अवैध बच्चों के स्वाभाविक संरक्षक हैं, केवल अपने मातृत्व के कारण, बिना किसी सूचना की आवश्यकता के। हमारे लिए यह रेखांकित करना उचित होगा कि हमारे निदेशक सिद्धांत एक समान नागरिक संहिता के अस्तित्व की कल्पना करते हैं, लेकिन यह एक अनुत्तरित संवैधानिक अपेक्षा बनी हुई है।

12. हम मानते हैं कि अपने बच्चे के जीवन में शामिल होने का पिता का अधिकार छीन लिया जा सकता है यदि धारा 11 को इस तरह से पढ़ा जाता है कि उसे नोटिस नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्चे के जीवन में

उसकी भागीदारी की कमी को देखते हुए, हम माँ या उसके बच्चे के अधिकारों पर उसके अधिकारों को प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही एक नोशनल डेली में एक प्रकाशन के माध्यम से आम जनता को नोटिस जारी कर चुका है और एक हलफनामा प्रस्तुत कर चुका है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी भी समय बच्चे के पिता को आपत्ति है तो उसके संरक्षकता अधिकारों को निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, पिता के अधिकारों, नहीं तो कर्तव्य को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है।

13. हाथ में मुद्दा अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या है। चूंकि अधिनियम का उद्देश्य बच्चे के कल्याण की रक्षा करना है, इसलिए धारा 11 की प्रयोज्यता को तदनुसार पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ 1985 (पूरक) एस. सी. सी. 701 में, इस न्यायालय ने गोद लेने वाले माता-पिता और बच्चे का पता लगाने से रोकने के लिए बच्चे के जैविक माता-पिता को संरक्षकता आवेदनों के नोटिस जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालाँकि अभिभावक और वार्ड अधिनियम उस मामले में प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित नहीं था, फिर भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोहराता है कि माता-पिता के अधिकारों सहित बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान मामले में हमें कोई संकेत नहीं मिलता है कि यदि अपीलकर्ता को पिता की पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है,

या यह कि बच्चे के हित में अदालत की सूचना अनिवार्य है, तो बच्चे के कल्याण को कम किया जाएगा। इसके विपरीत, हम पाते हैं कि यह बच्चे को सामाजिक कलंक और अनावश्यक विवाद से अच्छी तरह से बचा सकता है।

14. लक्ष्मीकांत पांडे की अनुपस्थिति में भी हम अनियंत्रित अशांत समुद्रों में नाविकों की तरह नहीं हैं। गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (1999) 2 एस. सी. सी. 228 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियों को आसानी से याद किया जाता है। आर. बी. आई. ने केवल माँ द्वारा हस्ताक्षरित बच्चे के नाम पर सावधि जमा के लिए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम की धारा 6 के साथ-साथ अभिभावक और वार्ड अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में, इस अदालत ने स्पष्ट किया था कि "उन सभी स्थितियों में जहां पिता नाबालिग के मामलों के वास्तविक प्रभारी नहीं हैं, या तो अपनी उदासीनता के कारण या उसके और नाबालिग की मां (मौखिक या लिखित) के बीच एक समझौते के कारण और नाबालिग मां की विशेष देखभाल और अभिरक्षा में है या पिता किसी अन्य कारण से नाबालिग की शारीरिक और/या मानसिक अक्षमता के कारण उसकी देखभाल करने में असमर्थ है, मां नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक के रूप में कार्य कर सकती है और उसके सभी कार्य नाबालिग

के जीवनकाल के दौरान भी मान्य होंगे, जिसे धारा 6 के उद्देश्यों के लिए" अनुपस्थित "माना जाएगा। इस न्यायालय ने हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम की धारा 6 (ए) में 'आफ्टर' शब्द का अर्थ "बच्चे के प्रति पिता की पूर्ण उदासीनता या बीमारी के कारण या अन्यथा पिता की अक्षमता की अनुपस्थिति में" के रूप में लिया है। इस प्रकार इस न्यायालय ने अपने समक्ष कानून की व्याख्या इस तरह से की कि माँ, जो एकमात्र शामिल अभिभावक थीं, को बच्चे पर संरक्षकता का अधिकार दिया जा सके।

15. ऐसे मामले में जहां माता-पिता में से एक अपने बच्चे के अभिभावक के रूप में नियुक्ति के लिए अदालत में याचिका दायर करता है, हम सोचते हैं कि धारा 11 के प्रावधान सीधे लागू नहीं होंगे। हमें ऐसा लगता है कि धारा 11 उस स्थिति पर लागू होती है जहां किसी बच्चे की संरक्षकता किसी तीसरे पक्ष द्वारा मांगी जाती है, जिससे गोद लेने के दौरान बच्चे के कल्याण के लिए बच्चे के स्वाभाविक माता-पिता के विचार प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। हमारी राय में, विवाह से पैदा हुए और केवल उसकी माँ द्वारा उठाए गए बच्चे के हितों की रक्षा के लिए एक असंबद्ध पिता के विचार आवश्यक नहीं हैं। हम दोहरा सकते हैं कि क़ानून की स्पष्ट शर्तों के बावजूद, इस अदालत ने लक्ष्मीकांत पांडे में निर्देश दिया था कि माता-पिता को नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इससे गोद लिए जा

रहे बच्चे के भविष्य और हित को खतरे में डालने की संभावना थी। इसलिए, माता-पिता के अधिकारों की परवाह किए बिना, हमारे सामने विचार करने के लिए एकमात्र कारक नाबालिग बच्चे का कल्याण है। हमें गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने पति या पत्नी में से एक द्वारा दूसरे पति या पत्नी के पीछे से शादी से बच्चे की अभिरक्षा लेने के एकतरफा प्रयास को अपनी अभेद्यता दी है। विद्वान न्यायमित्र श्री लूथरा की आशंकाओं को तदनुसार संबोधित किया जाता है।

16. धारा 11 विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है; हम अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकताओं में ढील देने में कोई नुकसान या बुराई नहीं देखते हैं। यह देखते हुए कि अधिनियम में "अभिभावक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हम इसकी व्याख्या अवैध बच्चों के मामले में करते हैं, जिनके एकमात्र देखभाल करने वाला उसके अभिभावक में से एक है, जिसका अर्थ मुख्य रूप से केवल वही अभिभावक है। संरक्षकता या अभिरक्षा आदेश कभी भी स्थायित्व या अंतिमता प्राप्त नहीं करते हैं और यदि बच्चे का कल्याण खतरे में है, तो नाबालिग बच्चे के लिए वास्तव में चिंतित किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय पूछताछ की जा सकती है। इसलिए असंबद्ध अभिभावक को संरक्षक न्यायालय से उसके आदेशों को रद्द करने, बदलने या संशोधित करने के लिए संपर्क करने से नहीं रोका जाता है यदि बच्चे का सर्वोत्तम हित ऐसा दर्शाता है। इस प्रकार

बच्चे की स्वाभाविक माँ द्वारा पसंद की गई संरक्षकता या अभिरक्षा याचिका के संबंध में अनुमानित पिता को सूचना देने की कोई अनिवार्य और अपरिवर्तनीय प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है, जिसकी वह एकमात्र देखभाल करने वाली है।

11. बच्चे के कल्याण की धारणा और विस्तार में निहित, इसके प्राथमिक सहवर्ती में से एक के रूप में, बच्चे को अपने अभिभावक की पहचान जानने का अधिकार है। इस अधिकार को अब बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में निर्विवाद मान्यता मिली है, जिसे भारत ने 11 नवंबर, 1992 को स्वीकार किया है। इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संदर्भ की सुविधा के लिए मुख्य प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत किया गया है -

अनुच्छेद 1-

वर्तमान अधिवेशन के प्रयोजनों के लिए, एक बच्चे का अर्थ है अठारह वर्ष की आयु से कम का प्रत्येक मनुष्य, जब तक कि बच्चे पर लागू कानून के तहत, वयस्कता पहले प्राप्त नहीं की जाती है।

अनुच्छेद 3

1. बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में, चाहे वे सार्वजनिक या निजी समाज कल्याण संस्थानों, अदालतों, प्रशासनिक प्राधिकरणों या विधायी निकायों द्वारा किए गए हों, बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर प्राथमिक विचार किया जाएगा।

2. राज्य पक्ष अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावकों या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की ऐसी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने का वचन देते हैं जो उसकी भलाई के लिए आवश्यक है और इसके लिए सभी उचित विधायी और प्रशासनिक उपाय करेंगे।

3. राज्य पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों की देखभाल या सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थान, सेवाएं और सुविधाएं सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप हों, विशेष रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, अपने कर्मचारियों की संख्या और उपयुक्तता के साथ-साथ सक्षम पर्यवेक्षण में।

अनुच्छेद 7

1. बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पंजीकृत किया जाएगा और उसे जन्म से ही किसी नाम का अधिकार, राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार

और जहां तक संभव हो, उसके माता-पिता द्वारा जानने और उसकी देखभाल करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 9

1. पार्टियां यह सुनिश्चित करेंगी कि एक बच्चे को उनके माता-पिता से उनकी इच्छा के खिलाफ अलग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जब न्यायिक समीक्षा के अधीन सक्षम अधिकारी लागू कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार यह निर्धारित करते हैं कि इस तरह का अलगाव बच्चे के सर्वोत्तम हितों के लिए आवश्यक है। इस तरह का निर्धारण किसी विशेष मामले में आवश्यक हो सकता है जैसे कि अभिभावक द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा, या जहां माता-पिता अलग रह रहे हैं और बच्चे के निवास स्थान के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।

2. वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार किसी भी कार्यवाही में, सभी इच्छुक पक्षों को कार्यवाही में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

3. राज्य पक्ष उस बच्चे के अधिकार का सम्मान करेंगे जो एक या दोनों अभिभावक से अलग है और नियमित रूप से दोनों अभिभावक के साथ व्यक्तिगत संबंध और सीधा संपर्क बनाए रखता है, सिवाय इसके कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हितों के विपरीत है।

अनुच्छेद 12

1. राज्य पक्ष उस बच्चे को जो अपने विचार बनाने में सक्षम है, बच्चे को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में स्वतंत्र रूप से उन विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का आश्वासन देंगे, बच्चे के विचारों को बच्चे की उम्र और परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व दिया जाएगा।

2. इस उद्देश्य के लिए, बच्चे को विशेष रूप से राष्ट्रीय कानून के प्रक्रियात्मक नियमों के अनुरूप तरीके से बच्चे को प्रभावित करने वाली किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही में, या तो सीधे, या एक प्रतिनिधि या एक उपयुक्त निकाय के माध्यम से, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

1. राज्य पक्ष इस सिद्धांत की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे कि बच्चे के पालन-पोषण और विकास के लिए माता-पिता दोनों की समान जिम्मेदारियां हैं। माता-पिता या, जैसा भी मामला हो, कानूनी अभिभावकों के पास बच्चे के पालन-पोषण और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। बच्चे का सर्वोत्तम हित उनकी मूल चिंता होगी।

अनुच्छेद 21

राज्य पक्ष जो गोद लेने की प्रणाली को मान्यता और/या अनुमति देते हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि विचार होंगे और वेः

(ए) यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को गोद लेना केवल सक्षम अधिकारियों द्वारा अधिकृत है जो लागू कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार और सभी प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि माता-पिता, रिश्तेदारों और कानूनी अभिभावकों से संबंधित बच्चे की स्थिति को देखते हुए गोद लेने की अनुमति है और यदि आवश्यक हो, तो संबंधित व्यक्तियों ने ऐसी परामर्श के आधार पर गोद लेने के लिए अपनी सूचित सहमति दी है जो आवश्यक हो।

अनुच्छेद 27

2. माता-पिता या बच्चे के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी क्षमताओं और वित्तीय क्षमताओं के भीतर, बच्चे के विकास के लिए आवश्यक जीवन की स्थितियों को सुरक्षित करें।

4. राज्य पक्ष राज्य के भीतर और विदेश से बच्चे के लिए वित्तीय जिम्मेदारी रखने वाले माता-पिता या अन्य व्यक्तियों से बच्चे के रखरखाव की वसूली को सुरक्षित करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे। विशेष रूप

से, जहां बच्चे के लिए वित्तीय जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति बच्चे से अलग राज्य में रहता है, राज्य पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में प्रवेश या ऐसे समझौतों के समापन के साथ-साथ अन्य उपयुक्त व्यवस्थाओं को बढ़ावा देंगे।

18. लक्ष्मीकांत पांडे में, इस न्यायालय ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के प्रावधानों को विधिवत नोट किया, लेकिन बच्चों को गोद लेने के सामान्य संदर्भ में और विशेष रूप से, परिणामी संरक्षकता/अभिरक्षा कार्यवाही में प्राकृतिक माता-पिता को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में। कन्वेंशन के जिन प्रावधानों को हमने निकाला है, वे वास्तव में इस स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराते हैं कि बच्चे का कल्याण न केवल भारत में कानून के संबंध में, बल्कि दुनिया भर के सभी क्षेत्राधिकारों में माता-पिता के कथित अधिकारों के लिए सर्वोपरि है। हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि हम वर्तमान में अभिरक्षा संघर्ष का सामना नहीं कर रहे हैं और इसलिए, अपने बच्चे के हितों और कल्याण के संरक्षक के रूप में अपीलार्थी की क्षमता या अन्यथा पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, हमें अपने माता-पिता के देशभक्त दायित्वों के प्रति दृष्टिकोण खोने से नफरत होगी, और इस संबंध में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चे के अपने माता-पिता की पहचान जानने के अधिकार को बेकार, कमजोर, समझौता या खतरे में न डाला जाए। इस

अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, हमने अपीलार्थी का साक्षात्कार लिया है और उसे अपने बेटे को पिता के नाम का खुलासा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उसने कुछ विवरणों के साथ उसके नाम का खुलासा किया है; वह कहती है कि उसे उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। इन विवरणों को एक लिफाफे में रखा गया है और विधिवत सील कर दिया गया है, और केवल इस न्यायालय के एक विशिष्ट निर्देश के अनुसार पढ़ा जा सकता है।

19. हम इस तथ्य से बहुत परेशान हैं कि अपीलार्थी ने अपने लगभग पाँच साल के बेटे के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। इससे भविष्य में बच्चे के लिए समस्याएं पैदा होनी तय है। इस संबंध में, अपीलार्थी ने हमारे समक्ष या नीचे दिए गए किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई राहत नहीं मांगी है। यह कानून में एक गलत धारणा है क्योंकि वर्तमान में यह माना जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करना अपीलार्थी के लिए उसकी संरक्षकता याचिका में सफल होने के लिए एक तार्किक परिणाम होगा। यह याद किया जा सकता है कि क्यूरियल फिएट के कारण, अब बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने के साथ-साथ नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदनों में पिता का नाम बताना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, इन दोनों मामलों में, अभी भी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है। कानून गतिशील है और उम्मीद की

जाती है कि वह समय और उसके द्वारा प्रस्तुत कानूनी पहेली और पहेली के साथ लगन से तालमेल बनाए रखेगा। इस बात का कोई खंडन नहीं है कि माँ की पहचान पर कभी संदेह नहीं होता है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि यदि कोई एकल माता-पिता/अविवाहित माँ अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करती है, तो संबंधित अधिकारी उसे केवल इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई अदालत का निर्देश न हो। हालांकि यह सामान्य है, फिर भी हम इस बात पर जोर देते हैं कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक को केवल इसलिए कोई असुविधा या नुकसान न हो क्योंकि माता-पिता जन्म का पंजीकरण करने में विफल रहते हैं या लापरवाही करते हैं। नहीं, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक जन्म को दर्ज करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। किसी भी संभावित संदेह को दूर करने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित निर्देश जानबूझकर परिस्थितियों या हमारे सामने आने वाले पक्षों तक ही सीमित नहीं है।

20. हम इस तथ्य को भी रेखांकित करना आवश्यक समझते हैं कि संरक्षक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय, जो अपील के दायरे में था, को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था कि उन्हें अपने

अभिभावक के अधिकार क्षेत्र का निर्वहन करने के लिए कहा गया था। न्यायालय के समक्ष संरक्षकता याचिका रखे जाने पर, संबंधित बच्चा अभिभावक की अनन्य अभिरक्षा में रहना बंद कर देता है; उसके बाद, जब तक वयस्कता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक बच्चा संरक्षकता में बना रहता है। एक ऐसी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के बाद जो एक बच्चे के भविष्य और कल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, नीचे दिए गए न्यायालयों को बच्चे से संबंधित सभी समस्याओं, जटिलताओं और परेशानियों पर विचार किए बिना केवल याचिका को खारिज करने में अपने कर्तव्य में लापरवाही के रूप में देखा जा सकता है।

21. इसलिए अपील की अनुमति है। संरक्षक न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को वापस ले और उसके बाद बच्चे के अनुमानित पिता को नोटिस दिए बिना संरक्षकता के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर तेजी से विचार करे।

निधि जैन अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक कैलाश पूनिया की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्कारण ही मान्य होगा।